



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 1995/आषाढ़ 26, 1917

No. 307]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 1995/ASADHA 26, 1917

कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1995

सा. का. नि. 551(अ):— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 4 की उपधारा (5) के माथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ:— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) “अध्यक्ष” से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ग) ऐसे शब्दों और पदों का जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. वेतन और भत्ते:—(1) उपनियम (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाए, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का आठ हजार रुपए प्रति मास वेतन संदत्त किया जाएगा:

परन्तु जहां अध्यक्ष या कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कोई शासकीय निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या अन्य स्वायत्त या कानूनी निकाय हो सेवानिवृत्त व्यक्ति है, वहां संदेय वेतन, उसके

पेंशन प्राप्त करने या पेंशनरीय फायदों का पेंशनिक मूल्य या दोनों सहित आठ हजार रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न आयोग में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार और उस मंत्रालय के परामर्श में होंगी :

(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, आयोग में अपनी नियुक्ति के समय, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, तो उसे अपना वेतन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन उसको लागू सेवा के नियमों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु तक प्राप्त करने का विकल्प होगा और उससे पश्चात् इन नियमों के उपबंध लागू होंगे।

4. पदानिर्णय—(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन पद से हटा नहीं दिया जाता, तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) यदि अध्यक्ष बीमारी या अन्य असमर्थता के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो केन्द्रीय सरकार, यदि आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष के पद धारण करने तक, धारण करेगा।

(3) यदि अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्ति होती है तो केन्द्रीय सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष का पद, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन रिक्ति होने तक नामनिर्देशन द्वारा भरे जाने तक धारण करेगा।

5. छुट्टी—अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित रूप में छुट्टी का हकदार होगा :—

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार उपाजित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी।

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, के अधीन अस्थायी सरकारी सेवाओं को यथा अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी।

(ग) जहां अध्यक्ष या सदस्य आयोग में अपनी नियुक्ति के पूर्व उसकी सेवा को शामिल करने वाले निबंधनों और शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए विहित मामान्य आयु अभिप्राप्त करने पर सेवानिवृत्त

होता है, वहां वह सेवानिवृत्ति की तारीख को अपने खाते में उपाजित छुट्टी, यदि कोई हो, के लिए अधिकतम 240 दिन के अधीन रहते हुए छुट्टी वेतन के नकद समतुल्य का हकदार होगा। ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजित किया जाता है, अपने पुनर्नियोजन की समाप्ति पर पुनर्नियोजन की समाप्ति की तारीख को अपने खाते में उपाजित छुट्टी की बाखत, अधिकतम 240 दिन के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत वह अवधि भी है जिसके लिए पूर्व सेवानिवृत्ति के समय उसे नकद लेने के लिए अनुज्ञात किया गया था, नकद समतुल्य का हकदार होगा।

टिप्पण :— उपाजित छुट्टी के नकद समतुल्य की संगणना केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

6. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी—अध्यक्ष को किसी सदस्य की छुट्टी मंजूर करने का प्राधिकार होगा और केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

7. अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्त—ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य के बारे में, जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की सेवा में था, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी सेवा से आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से सेवानिवृत्त हुआ है।

8. पेंशन (1) ऐसे अध्यक्ष या कोई सदस्य जो उस रूप में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की सेवा में था, नियम 7 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या अपनी अधिवर्षिता की तारीख को या उससे पहले, जो भी पूर्वतर हो, प्रयोग किए जाने वाले अपने विकल्प पर, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख में उस सेवा को, जिसका वह अंग था, लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे लेने का हकदार होगा।

(2) यदि ऐसा अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो उस रूप में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में था, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो वह उस सेवा को, जिसका वह ऐसी नियुक्ति के ठीकपूर्व अंग था, लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्त फायदों के लिए सदस्य के रूप में अपनी सेवा की गणना करेगा :

परन्तु सदस्य के रूप में सेवा की, उस सेवा के, जिसका वह अंग था, नियमों के अधीन केवल अधिवर्षिता की आयु तक, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों के लिए, इस प्रकार गणना की जाएगी।

9. भविष्य निधि—(1) ऐसा अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो उस रूप में आयोग में नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की सेवा में था और जिसे साधारण भविष्य निधि या अभिदायी भविष्य निधि के फायदों के लिए सम्मिलित किया गया था, अपने विकल्प पर, उस तारीख तक, जिसको वह सेवा में उसका लागू नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होता है उस निधि में अभिदाय करना जारी रख सकेगा अभिदायी भविष्य निधि की दशा में, उस निधि में संदेय नियोजक का अभिदाय आयोग में अध्यक्ष की या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से ही ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की अवधि के दौरान उन उपलब्धियों जिन्हें वह नियुक्ति के ठीक पूर्व उस पद पर जो वह धारण कर रहा था, प्राप्त करता के आधार पर आयोग द्वारा संदेय होगा।

स्पष्टीकरण:— इस उप नियम के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने विकल्प को लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को अपनी नियुक्ति के छह मास के भीतर सूचित करेगा और इस प्रकार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसने नियम 8(1) या नियम 9(1) के अधीन या दोनों के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, अभिदायी भविष्य निधि स्कीम के फायदों में सम्मिलित किए जाने का हकदार होगा और इस प्रयोजन के लिए वह समय-समय पर यथासंशोधित अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 द्वारा शासित होगा।

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य इस नियम के अधीन अभिदायी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित किए जाने की तारीख से किसी अन्य भविष्य निधि में अभिदाय करना बंद कर देगा।

10. विशेष प्रास्थिति प्रदत्त अध्यक्ष या सदस्यों की दशा में सेवा शर्तें इस नियम के उपबंधों में से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, यदि वह आवश्यक समझे, किसी ऐसी विशेष प्रास्थिति, जो पदधारी को प्रदत्त की जाए, के अनुसार अध्यक्ष या किसी सदस्य को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं संजूर कर सकेगी।

11. अवशिष्ट उपबंध—अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, वे होंगी जो भारत सरकार के सचिव को समय-समय पर लागू हैं।

[फा. सं. 1/7/5/94 एम सी (डी)]

भगवती प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1995

G.S.R. 551(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 read with sub-section (5) of section 4 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the

salary and allowance payable to and other terms and conditions of service of the Chairperson and Members of the National Commission for Minorities namely :—

1. Short title and commencement ; (1) These rules may be called the National Commission for Minorities (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992) ;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission.

(c) The words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Salary and allowance (1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), the Chairperson and every Member shall be paid a salary of rupees eight thousand per month :

Provided that where the Chairperson or a Member is a retired person from the Central Government or a State Government or Union Territory Administration or semi-Government body or public sector undertaking or a recognised research institution or other autonomous or statutory body, the salary payable together with the pension or pensionary value of he terminable benefits or both received by him shall not exceed eight thousand rupees per month.

Provided further that in case a retired Judge of Supreme Court or a High Court is appointed as a Chairperson or a Member of the Commission, the terms and conditions of service of such Chairperson or a Member shall be in accordance with the instructions issued by the Ministry of Finance in respect of appointment of Judges to various Commissions and in consultation with that Ministry.

(2) If at the time of his appointment to the Commission, the Chairperson or a Member is in service of the Central or a State Government, or Union Territory administration he shall have the option to receive his salary upon the age of superannuation in accordance with the rules of service applicable to him under the Central or a State Government or Union Territory administration, as the case may be and thereafter the provisions of these rules shall apply.

4. Tenure of office,—

(1) The Chairperson and every Member shall, unless removed from office under sub-section (3) of section 4 of the Act, hold office for a period not exceeding three years.

(2) If the Chairperson is unable to discharge his functions owing to illness or other incapacity, the Central Government if so required by the Commission, shall nominate any other Member to act as Chairperson and the Member so nominated shall

hold office of Chairperson until the Chairperson resumes office.

(3) If a vacancy occurs in the office of the Chairperson by reason of his death or resignation, the Central Government shall nominate any other Member to act as Chairperson and the Member so nominated shall hold office of Chairperson until the vacancy is filled by a fresh nomination under sub-section (4) of section 4 of the Act.

5. Leave—The Chairperson and every Member shall be entitled to leave as follows :

- (a) Earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time;
- (b) Extraordinary leave as admissible to the temporary Government servants under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time;
- (c) Where a Chairperson or Member retires on attaining the normal age prescribed for retirement under terms and conditions governing his service before his appointment to the Commission he shall be entitled to cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at his credit on the date of retirement subject to a maximum of 240 days. In case of Chairperson or Member who is re-employed after retirement shall, on termination of his re-employment be entitled to cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of termination of re-employment subject to a maximum of 240 days, including the period for which encashment was allowed to him at the time of earlier retirement.

Note : Cash equivalent of earned leave shall be computed in accordance with the provisions of CCS (Leave) Rules, 1972.

6. Leave sanctioning authority—The Chairperson shall be the authority to sanction leave to Member and the Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

7. Retirement from parent service on appointment as Chairperson or Member—The Chairperson or a Member who on the date of his appointment to the Commission was in the service of the Central or a State Government or Union Territory Administration shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as the Chairperson or a Member of the Commission.

8. Pension—(1) The Chairperson or a Member who, at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Government or Union Territory Administration shall without prejudice to rule 7 at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment in the Commission or on or before the date of his superannuation, whichever is earlier be entitled to draw his pension and other retirement benefits as per the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appoint-

ment as Chairperson or Member, as the case may be.

(2) If the Chairperson or a Member, who at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Government, or Union Territory Administration, does not exercise the option specified in sub rule (1) shall count his service as Member for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment.

Provided that service as member shall so count for pension and retirement benefits upto the age of superannuation only under the rules of service to which he belonged.

9. Provident Fund—(1) The Chairperson or a Member, who on the date of his appointment to the Commission as such was in the service of the Central or a State Government or Union Territory Administration and who had been admitted to the benefits of General Provident Fund or Contributory Provident Fund may at his option, continue to subscribe to that Fund until the date on which he retires according to rules applicable to him in service. In the case of the Contributory Provident Fund, the employer's contribution payable to that Fund shall as from the date of the Chairperson's or Member's appointment to the Commission be payable by the Commission during the tenure of appointment as such Chairperson or Member on the basis of the emoluments which he would have drawn in the past he held immediately before appointment.

Explanation : The Chairperson or a Member exercising his option under this sub-rule shall communicate his option in writing to the Central Government within six months of his appointment and the option so exercised shall be final.

(2) The Chairman or a Member including the person who has exercised an option under rule 8(1) or rule 9(1) or under both shall be entitled to be admitted to the benefits of the Contributory Provident Fund Scheme and for this purpose shall be governed by the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 as amended from time to time.

Provided that the Chairperson or Member shall case to contribute to any other Provident Fund from the date of admission to the Contributory Provident Fund Scheme under this rule.

10. Service conditions in the case of Chairperson or Members accorded special status—Without prejudice to any of the provisions in this Rule the Central Government may by order, if it is considered necessary sanction salaries, allowances and other facilities to the Chairperson or a Member in accordance with any special status that may be conferred on the incumbent.

11. Residuary Provision—The salaries, allowances and conditions of service of the Chairperson and the Members for which no express provision has been made in these rules will be as those applicable to a Secretary to the Government of India from time to time.

IF. No. 1/7/94 MC(D)
BHAGWATI PRASHAD, Jt. Secy.